

ईद, रामनवमी व सरहुल पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

प्रश्नपत्रिनिधि

मेदिनीनगर (पलामू)। जिले के उपायुक्त सह जिला दंडधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को ईद, रामनवमी व सरहुल पर्व के महोनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी। टाउन हाउस में आयोजित बैठक में जिलेभर में ईद, सरहुल व रामनवमी के त्योहार को पारंपरिक उत्साह, आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त श्री रंजन ने रामनवमी के अवसर पर विध्वंशव्याप्ति विभाग डाक्टरों की कोशिश करने के चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिये सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि पर्व में डॉज बजाने पर पूर्ण रूप से बंद रखने पर बल दिया साथ ही सभी रामनवमी जुलूस को रात 10 बजे तक समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था व पवित्रता के साथ मनाया जाता है यह स्पिलसिला जारी रहे। उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों को अपने स्तर से भी असामाजिक तत्वों पर नियरानी रखने की अपील की। बैठक में रामनवमी

डीसी-एसपी ने सभी से सामाजिक सौहार्द व आदर्श आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की

महासमिति के सदस्यों द्वारा बिजली व पेयजल से संबंधित उठाए गए समस्याओं को लेकर उपायुक्त ने नगर निगम, बिजली विभाग व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों को आपस में बैठक सम्पन्न बनाते हुए जुलूस रुट में पड़ने वाले सभी तरह के समस्याओं का निराकरण कराने की बात कही। उन्होंने तीनों एसडीओ को उनके क्षेत्र अंतर्गत निकलने वाले सभी जुलूस के साथ एक मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति करने व जुलूस के निगरानी हेतु सीसीटीवी लगान, बीड़ीयों ग्राफर की व्यवस्था रखने की बात कही। इसके पूर्व उन्होंने अनुमण्डलवार, अंचलवार वैयारियों की समीक्षा कर उनके द्वारा किये गये त्योहारों से अवानुष्ठान हुए।



निगरानी, महत्वपूर्ण स्थानों पर

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

ड्रोन पर पूर्ण रूप से बैन रखेगा इस

किया जायेगा ब्रैकिंग : उपायुक्त

माध्यम से पूरी तरह से स्कैन करने

लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि

ने सभी एसडीओ को जुलूस हुत

अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी

ड्रोन से हाँगी

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रैकिंग :

उपायुक्त

निर्धारित किए गए मार्गों को ड्रोन के

किया जायेगा ब्रै

आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। सोमवार को पारित इस प्रस्ताव में सभी बंधकों की अविलंब बिना शर्त रिहाई और गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की भी बात कही गई है। छह महीने से जारी इस

संपादकीय

दुआ कि अमेरिका ने इसे बीटो करने से परहेज किया। निश्चित रूप से
सुक्ष्मा परिषद का यह प्रस्ताव विश्व जनमत से उपजे दबाव की
अभिव्यक्ति है। पिछले सात अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए
आतंकी हमले के खिलाफ जब इस्लाइल ने कार्रवाई की बात कही तो

अमेरिका और भारत समेत तमाम देशों की सहानुभूति उसके साथ थी। लेकिन इस्साइल ने जिस तरह से गाजा में हवाई हमले शुरू किए और वहां से आम लोगों के हताहत होने की खबरें आने लगीं, उसके बाद यह आवाज तेज होती गई कि इस्साइल को अपने अधियायन का स्वरूप बदलना चाहिए। अब तक गाजा में करीब 32 हजार लोगों के मरे जाने की खबरें हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अफसोस की बात थी कि अलग-अलग देशों में हो रहे प्रदर्शनों में व्यक्त होती जनभावना

**भाजपा का कांग्रेसीकरण से संघ से दूर
तो नहीं हो रही है भाजपा, टिकट देने में
कथनी और करनी में अंतर**

सुखदेव प्रसाद अंटू

भाजपा के काग्रसाकरण से संघ से पार्टी कहीं अपने गठन, सिद्धांत और संघ से दूर तो नहीं हो रही है, यह बात भाजपा के भीतर से ही अब उठने लगी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी और से संघ से जुड़े वैसे कार्यकर्ताओं का टिकट काट देना या उनकी अनदेखी कर कांग्रेस या अन्य दलों से आये लोगों को जिस तरह दुष्प्रचार से लागा के दिला से कब उत्तर जाएगी यह पार्टी का शीर्ष नवतृत जबतक समझ पायेगा, तबतक काफी देर हो चुकी होगी। अब प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है, लेकिन एक के बाल एक कुछ फैसलों से यह कबतक बरकरार रह पायेगी, यह कोई नहीं जानता।

आज प्रश्न यह है कि महान नेता

जाज प्ररन पह है कि नहीं नहीं भारत-रन्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाजपाई राजनीति के उच्च मापदंड कायम किए थे, उसके परिषेक्ष्य में पार्टी कहाँ खड़ी है? निःसंदेह अटलजी एवं मोदी जी के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार ने ऐसे कई युगांतरकारी कदम उठाए हैं जिससे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगे। लेकिन सवाल आज यह है कि क्या भाजपा को अब पं.दीनदयाल, जयप्रकाश और अटलजी-प्रणीत उन नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक जीवन के उन आदर्शों की परवाह है?

उ अंतर्क्रिया १९८० का नई पिलाने की फिरोजशाह कोटला मैदान में जब जनता पार्टी के भगवानशेष पर भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी थी तो इस दक्षिणपंथी पार्टी का आधार आरएसएस और हिन्दुवादी संगठन, साफ- सुधरे लोग और पार्टी के समर्पित लोग हुआ करते थे। तब इस नव-सृजित दल के प्रतीक के रूप में हिन्दुओं में पवित्र और भगवान के प्रतीक के रूप में पूजे जानेवाले कमल को आधार बनाया गया था। उस वक्त दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी के प्रतीक चिह्न कमल की प्रशंसा में कसीदे पढ़े और अपनी लिखी रचना पेश की थी, जिसमें लिखा यह है हमारा कमल/सुंदर, स्वच्छ, स्तिंगधा। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ के स्पर्श से सर्वथा मुक! यह भी कहा था कि हम देश की गंदी राजनीति के कीचड़ में सुंदर-स्वच्छ कमल खिलाएंगे तो शायद उस समय अटलजी को यह अंदाज नहीं था कि उनकी मूल्याधारित स्वच्छ राजनीति की विरासत को भविष्य में इस तरह हाल कर दिया जाएगा। भाजपा राष्ट्रवाद की बात तो जोरों से करती है, लेकिन आंतरिक तौर पर जातिवाद और क्षेत्रवाद के दीमक से वह नहीं निकल पा रही है, जो उसके वैचारिक जड़ों को खोखला कर रहे हैं। खासकर झारखण्ड और बिहार जैसे प्रदेशों में।

राजनीति में नैतिक मल्यों की जिसपर चलकर वह देश की जनता का विश्वास जीतते हुए आज जिस ऊँचाई पर हुंची है, उसमें संघ और पार्टी के उन सच्चे कार्यकर्ताओं के बलबूते, जो हाल में पार्टी में ही रहे और इसे अपने खून और पसीने से सींचा। इसलिये नहीं कि एक दिन उनकी अनदेखी कर उन्हें दूध की मक्खी की तरह आउट कर दिया जाएगा। जो दल छोड़े और दूसरे दलों में मलाई मारे और फिर वापस हुए या फिर दूसरे दल से आए, वे ही समर्पित लोगों पर भारी पड़ गए। कहे तो आज भाजपा अंधी दौड़ में उन स्वयं स्वीकृत सिद्धांतों को तिलांजलि देती नजर आ रही है जो कि उसकी आंतरिक ताकत के स्रोत रखती हैं और जिसपर चलकर वह राजनीति के अखाड़े में कांग्रेस, समाजवादियों और कम्युनिस्टों को निर्णायक मात्र देने में सफल रही। हर राज्य में कमोवेश यहीं स्थिति बना दी गई है। अपने राज्य झारखण्ड की बात करे तो भाजपा में जो कुछ चल रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करें तो घोर निराशा ही हाथ लगेगी। राज्यसभा की बात करें या इस लोकसभा चुनाव की, पार्टी ने जो-जो प्रत्याशी तय किए, से लेकर उसके शुभर्चितकों में मतदाताओं के उत्साह पर जो पानी फिर गया है, उसका कारण क्या है? टिकटों के लिए नाम तय करते वक्त कैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के योगदानों को बिसरा कर बाहर से आये लोगों या दार्गा-

राजनीति या नारायण कूपों का प्रतिस्थापना का लक्ष्य लेकर चली भाजपा को बाहर से आये लोग तहस-नहस कर रहे हैं, जो हर चुनाव के बीतने के साथ पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दूर कर रही है। ऐसे में पैसेवाले और दागी लोगों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। यदि इसपर मंथन नहीं हुआ और यही स्थिति बनी रही तो कार्यकर्ताओं के या फिर पैसेवालों को प्राथमिकता दी गई साफ- सुधरी छवि कैसे आउट हो गए या उनसे किनारा कर लिया गया जिहांने वर्षों- दशकों से पार्टी के लिए अनन्य भाव से पसीना बहाया और यहाँ सबाल भाजपाईयों को दर्द दे रहा है, जो ईमानदारी से दल से लगे रहे और आज यह सबकुछ उन्हें देखना पड़ रहा है।

युद्धविराम की जस्तरत

सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पारिषद के प्रस्ताव के रूप में बाहर नहीं आ पा रहा था। खुद अमेरिका इससे पहले गोजा युद्ध विराम से जुड़े तीन प्रस्ताव को वीटी कर चुका था। सोमवार को मतदान से अलग रहते हुए भी उसने इस प्रस्ताव को पारित होने दिया, जो उसके अब तक के रुख में अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी रुख में आए इस कथित बदलाव पर इसाइल ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। इसाइली पीएम नेतर्याह ने इसी सप्ताह बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाले एक उच्चस्तरीय

प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि अमेरिका ने अपने रुख में बदलाव से इनकार किया है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि अमेरिका का ताजा कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसाइल उसके समर्थन को तय मानकर न छले। बेशक अमेरिका के रुख में यह बदलाव और सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन फिर भी इनके संभावित परिणामों को लेकर अभी कोई निर्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हालांकि अभी बात इसाइल और फलस्तीन के बेहद लंबे और जटिल विवाद की नहीं, बस गाजा में चल रहे युद्ध को बंद करने और बंधकों को रिहा करने की संभावनाओं तक सीमित है। लेकिन यह सीमित लक्ष्य भी तमाम अनिश्चितताओं से धिरा है। ऐसे में फिलहाल सिर्फ यह उमीद और अपील की जा सकती है कि सभी संबंधित पक्ष इस मामले में पॉजिटिव और लचीला रुख अपनाएं।

एआईकीमद्दसेभारत,अमेरिकावदक्षिण कोरियाकेचुनावोंकोप्रभावितकरनेकीसंभावना?

साधियों बात अगर हम एक तकनीकी दिग्गज के आंकलन की करें तो, भारत और अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान चीन अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित सामग्री का उपयोग कर सकता है। प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक ब्लॉग में यह आशंका जताई। ब्लॉग में कहा गया, हमारा आंकलन है कि विशेष रूप से भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका सहित इस साल दुनियाभर में होने वाले आम चुनावों के दौरान चीन अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए एआई आधारित सामग्री का निर्माण और प्रसार कर सकता है। रिपोर्ट में उत्तर कोरिया ई साइबर जोखिम तत्वों का भी उल्लेख किया गया, जो इन तीन देशों में चुनावों को प्रभावित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के निष्कर्षों के अनुसार, चीन द्वारा एआई आधारित सामग्री का उपयोग करने से चुनाव परिणामों के प्रभावित होने की आशंका कम है, लेकिन इनके लगातार उपयोग, मीम्स के प्रसार आदि से भविष्य में इनका असर हो सकता है।



चतावना दा है, जिस रखाकित करना समय की मांग है। चूंकि भारत में 19 अप्रैल 2024 से प्रथम चरण के चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ अमेरिका में इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भूराजनीतिक हितों को बढ़ावा देने चीन द्वारा भारत अमेरिका चुनावों को लक्षित करने एआई का दुरुपयोग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

साथियों बात अगर हम भारत अमेरिका जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में एआई सामग्री के दुरुपयोग की आशंका की करें तो, एक तकनीकी दिग्गज ने चेतावनी दी है कि चीन भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में चुनावों के दौरान अपने भू-राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जनता की राय को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-जनित सामग्री को तैनात कर सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली ऐसी सामग्री की संभावना कम होने के बावजूद, मीम्स, वीडियो और ऑडियो को बढ़ाने में चीन का बढ़ता प्रयोग संभवतः जारी रहेगा और भविष्य में और अधिक प्रभावी साबित हो सकता है, उन्होंने लिखा चीन उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ऐसा करेगा। ये कंपनी एक थ्रेट एनालिसिस सेंटर (एमटीएसी) द्वारा बुधवार को प्रकाशित नवीनतम पूर्वी एशिया रिपोर्ट में कंपनी थ्रेट इंटेलिजेंस अंतर्रूढ़ि में से एक है।

हता का लाभ पुरुचान के लिए एआई आधारित सामग्री का निर्माण और प्रसार कर सकता है। रिपोर्ट में उत्तर कोरियाई साइबर जोखिम तत्वों का भी उल्लेख किया गया, जो इन तीन देशों में चुनावों को प्रभावित करने की दिशा में काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के निष्कर्षों के अनुसार, चीन द्वारा एआई आधारित सामग्री का उपयोग करने से चुनाव परिणामों के प्रभावित होने की आशंका कम है, लेकिन इनके लगातार उपयोग, मीम्स के प्रसार आदि से भविष्य में इनका असर हो सकता है। ब्लॉग में कहा गया, ऐसी सामग्री के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की आशंका कम होने के बावजूद, चीन इन मीम, वीडियो और ऑडियो का प्रसार बढ़ाता रहेगा और भविष्य में ये अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। चीन भूरजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत, अमेरिका में चुनावों को लक्षित करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर सकता है।

साथियों बात अगर हम तीन देशों में होने वाले आबादी चुनाव में साइबर अभिकर्ताओं के लक्षित दिशा में काम की संभावना की करें तो, रिपोर्ट में कहा गया है, इस बीच, जैसे जैसे भारत, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में आबादी चुनाव की ओर बढ़ रही है, हमें चीनी साइबर और प्रभाव अभिनेताओं और कृष्ण हृद तक उत्तर कोरियाई साइबर अभिनेताओं को इन चुनावों को लक्षित करने की दिशा में काम करते हुए देखने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि धान कम से कम एआई-जनित सामग्री बनाएगा और बढ़ाएगा, जिससे इन हाई-प्रोफाइल चुनावों में उसकी स्थिति को फायदा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि चीनी साइबर अभिनेताओं ने लंबे समय से अमेरिकी राजनीतिक संस्थानोंकी टोह ली है, हम प्रभावशाली अभिनेताओं को अमेरिकियों के साथ बातचीत करने और अमेरिकी राजनीति पर संभावित शोध परिप्रेक्ष्य देखने के लिए तैयार हैं। आखिरकार, जैसा कि उत्तर कोरिया नई सरकारी नीतियों पर काम कर रहा है और हथियारों के परीक्षण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, हम रक्षा क्षेत्र पर लक्षित तेजी से परिष्कृत क्रिप्टोकरेंसी डकैतियों और आपूर्ति श्रृंखला हमलों की उम्मीद कर सकते हैं, जो शासन में धन पहुंचने और नए विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे। अतः अगर हम ऊपर पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत अमेरिका व दक्षिण कोरिया में 2024 में होने वाले चुनावों को एआई आधारित सामग्री से प्रभावित करने की संभावना? भू-राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने चीन द्वारा भारत अमेरिका चुनावों को लक्षित करने एआई का दुरुपयोग करने की आशंका? एआई आधारित सामग्री से चुनावों को प्रभावित करने तकीनी दिग्गज की चेतावनी को रेखांकित करना अब समय की मांग भी है।

आप के आदर्श शिक्षा मॉडल की स्थिति चिन्तनीय

ललित गर्ग

देश ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में दिल्ली की अरविंद के जरीवाल सरकार ने अपने शिक्षा मॉडल को अनुकरणीय बताया एवं अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में बहुप्रचारित किया लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में इसकी पोल खुल गयी। न्यायालय ने दिल्ली की स्कूलों की स्थिति अत्यंत चिन्तनीय, दुखद एवं अपर्याप्त बताते हुए दिल्ली के शिक्षा सचिव को फटकार लगायी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रौत्तम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट, ए सिविल राइट्स ग्रुप' का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अशोक अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत इस विषयक एक तीनों रिपोर्ट पर संज्ञान, सुनवाई एवं जांच में पाया फैदा। इन स्कूलों में कई विसंगतियाँ हैं जैसे टूटी हुई डेस्क, कक्षाओं की गंभीर कमी, पीने के स्वच्छ पानी का अभाव, अपर्याप्त किताबें और लेखन सामग्री। कई स्कूलों टिन बिलिंग में चल रही हैं एक स्कूल में 1,800 लड़कियाँ और 1,800 लड़के डबल शिप्ट में पढ़ते हैं। कुछ कक्षाओं में दो-दो कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। जब शिक्षा सचिव ने बदहाली की पुष्टि की तो जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आपकी इसी लापरवाही की वजह से तिहाड़ जेल में समस्या और भीड़ दोनों बढ़ी है। तिहाड़ जेल में दस हजार कैदियों की क्षमता है, लेकिन वहां 23 हजार हैं। वजह अशिक्षा एवं दूषित शिक्षा है जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य को बर्बाद हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाला ही नहीं, शिक्षा घोटाला

भी किया है।
केजरीवाल सरकार ने अपनी उपलब्धियों के नाम पर
दो उपक्रम प्रमुखता से गिनाये हैं एक शिक्षा एवं
दूसरा मुहल्ला कर्तीनिक। दिल्ली के सरकारी स्कूलों
की दशा एवं दिशा न केवल बिगड़ी है, बल्कि
रसातन में चली गयी है। मौहल्ला कर्तीनिकों व
स्थिति भी दयनीय है। दिल्ली से शुरू हुई उन्नत शिक्षा
की पहल को देश के अन्य प्रांतों ही नहीं, बल्कि
दुनिया के अनुकरणीय बताने वाले केजरीवाल
शिक्षा के बुनियाद क्षेत्र को भी भ्रष्टाचार की भें
चढ़ा दिया। शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र को राजनीति
नजरिये से देखना एवं उन्नत इंसानों को गढ़ने व
इस प्रयोगशाला से खिलावड़ करना, शर्मनापूर्ण
घटनाक्रम है। आप की सरकार ने साल 2015
साल 2024 के बीच 'शिक्षा सबसे पहले' एवं
एजूकेशन 'फर्स्ट' जैसा आकर्षक नारा देकर दिखा
सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नई जान फूक
के नाम पर दिखाया किया। कुछ स्कूलों व
अत्याधुनिक बनाकर दिल्ली की समस्त स्कूलों व
कायाकल्प करने की बात करने वाली केजरीवा
सरकार ने करोड़ों रुपये विज्ञापनों पर खर्च किये।
आप सरकार ने शिक्षा मंत्रालय संभाले उनकी
नायब/उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व
शिक्षा के लिए अधिकतम राशि का आवंटन किया
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की नई तकनीक और
विद्यार्थियों के वास्ते नए पाठ्यक्रम लागू किए तथा
स्कूलों का दम तोड़ा बुनियादी ढांचा सुधारे दिया
लिए जी खोल कर धन मुहैया कराया। लेकिन
दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई दिल्ली व
स्कूलों की दर्दनाक स्थितियां बताती है कि व

सरकारी खजाना अगर स्कूलों में खर्च होता तो स्कूलों की यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। स्पष्ट है स्कूलों के नाम पर आवटिट बजट में बड़े घोटाला हुआ है, उसकी स्वतंत्र जांच होनी ही चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय में ही एक अन्य याचिका में यह तथ्य भी सामने आया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छह लाख से ज्यादा बच्चों की शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं जैसे यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री इत्यादि नहीं मिल पा रही हैं। याचिका में कहा गया है कि राइट ऑफ चिल्डरन टू फ़ी एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट दिल्ली राइट ऑफ चिल्डरन टू फ़ी एंड कंपल्सरी रूल्स और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के नियमों के मुताबिक बच्चों को शिक्षण सत्र के शुरू में ही उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री इत्यादि सुविधाएं मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया है दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,69,488 छात्र और दिल्ली नगर निगम में पढ़ने वाले 3,83,203 छात्र शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिलने वाले वैधानिक सुविधाओं से वर्चित हैं। याचिका में 14 नवंबर 2023 के अंडिट मेमो का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2016-17 से शिक्षण सत्र से दिल्ली नगर निगम के छात्रों को वैधानिक वित्तीय सुविध नहीं दी जाती है। बिडम्बना देखिये दुनिया के लिये आदर्श मॉडल के रूप में दिल्ली की सरकारी स्कूलों को प्रचारित करने वाली स्कूलों की स्थिति कितनी खतरनाक है। स्कूल में एक ही कमरे के साइंस लैब, आर्ट रूम और लाइब्रेरी के तौर पर

प्रयोग किया जा रहा है। एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे हैं। दोनों पालियों में लगभग 4 हजार छात्र-छात्राएं यहां पढ़ते हैं। स्कूल में कुल 15 कमरे हैं लेकिन अधिकारिक तौर पर 7 साल पहले इस स्कूल को असुविधित घोषित किया गया है। देल्ही के मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल के उस शिक्षण मॉडल की जिसका डंका वे दिन रात बजाते हैं यहां तक कि न्यूयार्क टाइम्स में भी दिल्ली के शिक्षण मॉडल की तारीफों के पुल बांधते हुए लेख लिखे जाते हैं। उस शिक्षण मॉडल का यथार्थ बहुत भद्र एवं खौफनाक है। शिक्षा के नाम पर एक बदनुम्हा दाग है। जिसकी झलक प्रजा फाउंडेशन एनजीओ की क्वाइट पेपर रिपोर्ट में मिलती है। यह रिपोर्ट केजरीवाल के दावे को मुंह चिढ़ा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के सत्तम में आने के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। साल 2014-15 में सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट जहां 2.9 प्रतिशत था, दो साल के भीतर 2016-17 तक आते आते ड्रॉप आउट रेट 3.4 प्रतिशत हो गया दिल्ली ईकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में दिए गए आंकड़े मुख्यमंत्री के प्रचारतंत्र से वादा खिलाफ़ कर रहे हैं। ये आंकड़े सरकार पर सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधार रही है तो साल दर साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट क्यों रही है। ईकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2014-15 में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15.42 लाख थी जो घटते-घटते 2017-18 में 14.81 लाख रह गई।

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो रिपोर्ट जारी किया उसमें स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी, डॉप आउट, छात्र-शिक्षक अनुपात जैसी समस्या सामने उभर कर आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के छात्रों में सीखने की क्षमता राष्ट्रीय औसत से कम है। सरकारी स्कूल में दाखिले के विपरीत प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि आई है। साल 2014-15 में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 13.47 लाख थी जो 2020-21 में बढ़ कर 17.82 लाख हो गई। यानी 2014-15 से लेकर 2020-21 तक 6 साल के अंतराल में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में जहां 4 लाख 85 की वृद्धि हुई, वहीं सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में महज 78 हजार की वृद्धि हुई। आप की 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर से लगातार जबरदस्त जीत में सरकारी विद्यालय प्रणाली में सुधार के झूठे एवं भ्रामक दावों का जबरदस्त हाथ है, लेकिन अब इसकी सच्चाई धीरे-धीरे परत-तर-परत खुलने लगी है। आजादी का अमृत काल में दिल्ली को सरकारी स्कूलों का गिरता शिक्षा स्तर एवं बुनियादी सुविधाओं का अभाव आप सरकार पर एक बदनुमा दाग है, एक बड़ी नाकामी का घोटाला है। प्रश्न है कि किसे फिक्र है हमारी शिक्षा की? प्रश्न यह भी है कि झूठे प्रचार एवं दावों के बल पर आप सरकार कब तक दिल्ली की भोली-भाली जनता को गुमराह करती रहेगी? स्कूली शिक्षा में 'क्रांति' लाने के आप के दावे बच्चों के भविष्य से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे?

संक्षिप्त समाचार

सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर खट्टरगे ने जताई आपत्ति, दास्तावधारी दौपीटी मुर्मुकों को लिया चिह्न।

नईदिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खगे ने बुधवार को राष्ट्रपति दौपीटी मुर्मुकों को पत्र लिखकर स्कूलों के निजीकरण का आरोप लगाया। खगे ने साधारणता को निखे पत्र में बताया है कि सैनिक स्कूलों के निजी हाथों में देने से जुड़ी यह जनकारी सूचना के अधिकार (आरएआई) के तहत मार्गी गई जनकारी के जरिए सामने आयी है। खगे ने कहा कि जो जनकारी सामने आयी है, उसके तहत सरकार ने अब तक ऐसे 40 सैनिक स्कूलों को खोलने को लेकर निजी हाथों के साथ व संस्थाओं के साथ एमओयू किया है। खगे ने कहा कि इसमें से 62 फौसद से अधिक एमओयू बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हाथों के साथ एक एमओयू है। इनमें मुख्य मंत्री लोगों के साथ, कई विधायक, भजपा व आरएसएस पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम को सैन्य बलों के भीतर एक विचारधारा को थोकने की कोशिश बताया है। साथ ही कहा है कि सैन्य बलों को किसी राजनीतिक सोच या विचारधारा से दूर रखने की जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रहित को देखते हुए कप्रिया पार्टी इस पहल को तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

हैदराबाद में ऑनलाइन आईपीएल

सद्बेबाजी ऐकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने सद्बेबाजों से 40 लाख किए बरामद

हैदराबाद। हर साल आईपीएल का गेम होता है और हर साल इस गेम के बढ़ते रोमांच के बीच ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के आरोप कई लोग आते हैं। इस बार भी आईपीएल शुरू हो चुका है और उनके साथ सद्बेबाजी भी। हैदराबाद की साइबरबाबाद पुलिस ने चार सद्बेबाजों की गिरफतारी के साथ एक ऑनलाइन क्रिकेट सद्बेबाजी ऐकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को सचना मिली थी कि मियापुर पुलिस स्टेशन की सीधा के तहत मारुती नार के एक अपार्टमेंट आईपीएल 2024 में सद्वेबाजन का खेल चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने आपार्टमेंट के साथ एक ऑनलाइन क्रिकेट सद्बेबाजी ऐकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को आपार्टमेंट के साथ एक ऑपीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल

नईदिल्ली, एजेंसी।

राजधानी दिल्ली में पारा एक बार फिर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज और बाल यानी शुक्रवार को तापमान में और इजाजा हो सकता है और गर्मी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

वहीं, यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब में गर्मी में राहत मिलने के असार हैं। हालांकि, दो दिन से लोगों को हवा में गर्मी हटा सकती है। दिल्ली में दो दिनों से तापमान में इजाजा देखने को मिल सकती है।

दिल्ली में इन दिनों सुख हो से ही तेज धूप निकल रही है। इसके चलते तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है कि अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बीच अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। इस दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। हालांकि शनिवार की सामना के बाद दिल्ली के मौसम पर एक पश्चिमी विशेष धूप आपैल को भी आंधी बारिश का देखने को मिल रही है।

पौरी विभाग की मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी के साथ दिल्ली-एसीसीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल



को भी हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। इसके चलते तापमान में 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है।

दिल्ली में इन दिनों सुख हो से ही तेज धूप निकल रही है। इसके चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि, आसमान सफाहों और ठंडी हवा के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह रहा है। मानक वेशालाना सफदरजांग के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार का दिन सीजन के सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1

डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है जबकि, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से तीन डिग्री कम है।

दिल्ली में आर्द्धता का स्तर 55 से 26 फौसदी दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बीच अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है कि अनुमान है। इस दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। हालांकि शनिवार की सामना के बाद दिल्ली के मौसम पर एक पश्चिमी विशेष धूप आपैल को भी आंधी बारिश का देखने से रुक रहा है। इन दौरान लोगों को मिल रही है।

पौरी विभाग के मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी के साथ दिल्ली-एसीसीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल

को 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं और गरज चम्पक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग की मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी बारिश के साथ वारश का देखने को मिल रही है। इन दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। जबकि, आसमान सफाहों और ठंडी हवा के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह रहा है। मानक वेशालाना सफदरजांग के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार का दिन सीजन के सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1

डिग्री कम होने की वजह से तीन डिग्री

हवाएँ चलने की चेतावनी जारी की गई।

साथ ही गरज चम्पक के साथ वारश भी हो गया है। इन दौरान लोगों को मिल रहा है।

पौरी विभाग के मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी के साथ दिल्ली-एसीसीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल

को 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं और गरज चम्पक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग की मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी बारिश के साथ वारश का देखने को मिल रही है। इन दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। जबकि, आसमान सफाहों और ठंडी हवा के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह रहा है। मानक वेशालाना सफदरजांग के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार का दिन सीजन के सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1

डिग्री कम होने की वजह से तीन डिग्री

हवाएँ चलने की चेतावनी जारी की गई।

पौरी विभाग के मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी के साथ दिल्ली-एसीसीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल

को 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं और गरज चम्पक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग की मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी बारिश के साथ वारश का देखने को मिल रही है। इन दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। जबकि, आसमान सफाहों और ठंडी हवा के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह रहा है। मानक वेशालाना सफदरजांग के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार का दिन सीजन के सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1

डिग्री कम होने की वजह से तीन डिग्री

हवाएँ चलने की चेतावनी जारी की गई।

पौरी विभाग के मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी के साथ दिल्ली-एसीसीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल

को 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं और गरज चम्पक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग की मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी बारिश के साथ वारश का देखने को मिल रही है। इन दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। जबकि, आसमान सफाहों और ठंडी हवा के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह रहा है। मानक वेशालाना सफदरजांग के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार का दिन सीजन के सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1

डिग्री कम होने की वजह से तीन डिग्री

हवाएँ चलने की चेतावनी जारी की गई।

पौरी विभाग के मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी के साथ दिल्ली-एसीसीआई के कई इलाकों में हल्की बूंदबांदी की संभावना है। वहीं, 14 और 15 अप्रैल

को 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं और गरज चम्पक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग की मार्गे ने 13 अप्रैल को आंधी बारिश के साथ वारश का देखने को मिल रही है। इन दौरान लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। जबकि, आसम